



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

हस्ताक्षरित, सीलबंद और निर्यात शुरू भारत के व्यापार समझौते अपने कार्य की ओर अग्रसर

अगस्त 18, 2026

भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के नेटवर्क का विस्तार करने से लेकर बाजार तक पहुंच का पूरा इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहा है। मौजूदा निर्यात प्रदर्शन एफटीए साझेदारों के बढ़ते वाणिज्यिक महत्व को दर्शाता है। निर्यात में शुरुआती तेजी, तरजीही सीओओ जारी करने में वृद्धि और इन बाजारों में निर्यात की विस्तृत रेंज में बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इससे संकेत मिलता है कि अधिक से अधिक कारोबार इन समझौतों से पैदा होने वाले अवसरों का लाभ उठाना शुरू कर रहे हैं। निर्यातकों को तरजीही लाभ प्राप्त करने और नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद करने वाली सरकारी पहलों से भी इस बदलाव को सहयोग मिल रहा है।

भारत के एफटीए निर्यात का परिदृश्य

बीते एक दशक में, भारत ने अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और दूरदर्शी व्यापार रणनीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत उसने अपने **मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के नेटवर्क का विस्तार** किया है। प्रत्येक समझौता भारतीय बाजार के विशाल आकार, देश की आर्थिक क्षमता और 1.4 बिलियन लोगों की क्षमताओं में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को दर्शाता है।

हाल ही में हुए व्यापार समझौते प्रमुख वैश्विक बाजारों तक फैले हुए हैं, जिससे व्यापार साझेदारी का विस्तार हुआ है और निर्यातकों के लिए कई अवसर पैदा हुए हैं।

INDIA'S GROWING TRADE AGREEMENT PARTNERSHIPS



India Mauritius CECPA:
signed February, 2021



India-UK CETA:
signed July 2025

India-UAE CEPA:
signed February, 2022



India-Oman CEPA:
signed December 2025

India-Australia ECTA:
signed April, 2022



**India-European Union
FTA: negotiations
concluded 27th January 2026**

**India-European Free
Trade Association TEPA:**
signed March 2024



India-New Zealand FTA:
signed April 2026

नए समझौतों के साथ ही, भारत उनके **प्रभावी इस्तेमाल** पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका उद्देश्य इस बिंदु पर है कि बाजार तक पहुंच को व्यापक निर्यात भागीदारी, निवेश और रोजगार में परिवर्तित किया जाए, साथ ही घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा भी की जाए। इस संतुलित **दृष्टिकोण का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा में मुक्त व्यापार समझौतों के योगदान को सुदृढ़ करना है।**

एफटीए बाजार में निर्यात प्रदर्शन

भारत का बढ़ता व्यापार समझौता नेटवर्क निर्यातकों को कई बाजारों से जोड़ता है। देश के बढ़ते निर्यात आधार से इस विस्तार को बल मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में, कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात **रिकॉर्ड 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया, जिसमें **441.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्तु निर्यात** शामिल है। वित्त वर्ष 2026-27 में भी यह गति जारी रही।

- अप्रैल-जून 2026 के दौरान, संयुक्त निर्यात **232.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहने का अनुमान है, जो बीते वर्ष की इसी अवधि की तुलना में **11.37%** अधिक है।

इस समग्र निर्यात प्रदर्शन में, भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के साझेदार देश माल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बाजार हैं।

तालिका 1: एफटीए साझेदारों को भारत का माल निर्यात (2025-26)	
एफटीए बाजार	निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
एफटीए समूह	
आसियान	38,416.33
एसएएफटीए	25,774.68
एफटीए राष्ट्र	
संयुक्त अरब अमीरात	37,359.11
यूनाइटेड किंगडम	13,444.19
सिंगापुर	11,863.66
नेपाल	7,447.11
ऑस्ट्रेलिया	7,284.17
मलेशिया	6,825.55
जापान	6,039.50
दक्षिण कोरिया	6,012.03
श्रीलंका	5,516.83

थाईलैंड	5,058.60
ओमान	4,021.48
भूटान	1,252.86
न्यूजीलैंड*	566.51
मॉरीशस	473.64
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	*हस्ताक्षरित होना अभी बाकी है

इन बाजारों में, यूएई और ऑस्ट्रेलिया भारत के हाल ही में व्यापार समझौतों के अंतर्गत हुई शुरुआती प्रगति का उदाहरण हैं।

भारत की नई-पीढ़ी के एफटीए: शुरुआती सफलता की कहानियां
भारत-यूएई सीईपीए: व्यापारिक लाभ की हुई शुरुआत भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) 1 मई 2022 को लागू हुआ। यह एक दशक में भारत का पहला पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता था, जिस पर वार्ता रिकॉर्ड 88 दिनों में पूरी हुई। सबसे बड़ा निजी एफटीए निर्यात बाजार: भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में यूएई को 37,359.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात किया। भारत के व्यापार समझौतों में, यूएई भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार: वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 100.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया, जिसमें 19.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उपलब्धि समझौते के लागू होने के तीन साल के भीतर ही हासिल कर ली गई। व्यापक साझेदारी से मिली सफलता: द्विपक्षीय व्यापार में मिली सफलता के बाद, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक व्यापार को दोगुना करके 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए: एक सफल व्यापार साझेदारी का विस्तार भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ईसीटीए) 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ। ईसीटीए एक दशक से अधिक समय में किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। निर्यात में मजबूत प्रदर्शन: वित्त वर्ष 2024-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 80%+ की तेजी दर्शाता है। पूर्ण शुल्क-मुक्त बाजार तक पहुंच: ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 98.3% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान की। 2026 से, सभी भारतीय निर्यात ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शून्य-शुल्क पहुंच के लिए पात्र होंगे। नई पहलों के माध्यम से सफलता: ईसीटीए एक अधिक महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की नींव प्रदान करता है, जिस पर वर्तमान में चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, गतिशीलता, डिजिटल व्यापार, मूल नियमों और सहयोग के उभरते क्षेत्रों को शामिल करना है।

शुरुआती लाभ टैरिफ रियायतों के बढ़ते इस्तेमाल और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की व्यापक श्रेणी में भी परिलक्षित होते हैं। ये दर्शाते हैं कि व्यवसाय इन समझौतों द्वारा निर्मित अवसरों का तेजी से लाभ उठा रहे हैं।

मौजूदा एफटीए के अंतर्गत निर्यात सुविधा और उत्पाद विविधीकरण

निर्यातकों को एफटीए लाभ तक पहुंच प्रदान करना

व्यापार समझौता तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करता है, जबकि इसका व्यावहारिक इस्तेमाल निर्यातकों की ओर से उपलब्ध लाभ का दावा करने पर निर्भर करता है। एफटीए के तहत, निर्यातकों को आमतौर पर अपने माल के मूल का प्रमाण देना होता है। इससे समझौते के तहत उपलब्ध तरजीही टैरिफ व्यवस्था के लिए उनकी पात्रता स्थापित होती है।

तरजीही मूल प्रमाण पत्र (सीओ) इस बात की पुष्टि करता है कि माल निर्धारित मूल नियमों को पूरा करता है। इससे योग्य माल पर कम या शून्य सीमा शुल्क लागू होता है।

विभिन्न कार्यान्वयन चरणों में समझौतों में तरजीही पहुंच का इस्तेमाल किया जा रहा है।

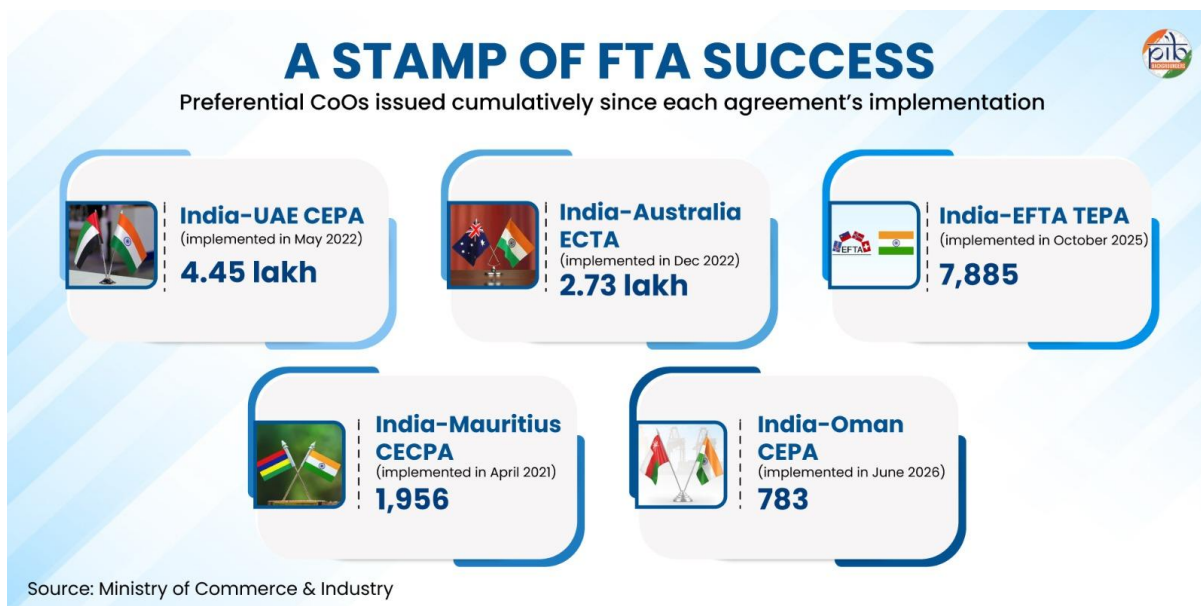
- संयुक्त अरब अमीरात के सीईपीए और ऑस्ट्रेलिया के ईसीटीए, जो 2022 से लागू हैं, ने बड़ी संख्या में मूल प्रमाणन (सीओ) जारी किए हैं, जो टैरिफ रियायतों के मजबूत इस्तेमाल को दर्शाता है।
- नए समझौतों के अंतर्गत भी तेज इस्तेमाल देखा गया है। ईएफटीए टीईपीए के अक्टूबर 2025 में लागू होने के बाद **7,885** सीओओ जारी किए गए। ओमान सीईपीए के जून 2026 में लागू होने के बाद **783** सीओओ जारी किए गए हैं।

निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने वाले सरकारी तरीकों से रियायती सीओओ जारी करने में बढ़ोतरी को सहयोग मिला है।

1. **ई-सीओओ 2.0:** यह प्रणाली रियायती और गैर-रियायती सीओओ के आखिरी छोर तक डिजिटल जारीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे निर्यातक, जारीकर्ता एजेंसियां और वाणिज्य मंडल एक साझा मंच पर आ जाते हैं। आधार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और क्यूआर-कोड सत्यापन सुरक्षित प्रमाणीकरण और त्वरित सेवा वितरण में मददगार होते हैं।
2. **मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सरलीकृत नियम:** नए समझौतों के तहत दस्तावेजीकरण संबंधी जरूरतों को भी सरल बनाया गया है।
 - भारत-ईएफटीए टीईपीए और भारत-यूके सीईटीए निर्यातकों को स्व-घोषणा के माध्यम से मूल स्थान स्थापित करने की अनुमति देते हैं।
 - यूके समझौता आयातक की जानकारी को भी मान्य करता है और **£1,000** से कम के माल के लिए मूल स्थान संबंधी दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को माफ करता है। ये प्रावधान ई-कॉमर्स शिपमेंट और छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करते हैं।
 - भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए एक ही सीओओ में कई योग्य उत्पादों को शामिल करने की मंजूरी देता है।
3. **ट्रेड कनेक्ट के माध्यम से सहायता:** यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को एफटीए के लाभों को पहचानने और उनका इस्तेमाल करने में मदद करके उपरोक्त उपायों का पूरक है। इसका टैरिफ एक्सप्लोरर विभिन्न बाजारों में टैरिफ अनुसूचियों तक पहुंच प्रदान करता है। एमएसएमई सहित निर्यातक व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं,



मार्गदर्शन ले सकते हैं और सीओओ से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं, जिससे निर्यात प्रक्रियाओं को समझने में लगने वाला समय कम हो जाता है।



मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाजारों में उत्पादों की व्यापक श्रृंखला की पहुंच

एफटीए की पहुंच साझेदार बाजारों में प्रवेश करने वाले उत्पादों की श्रृंखला में भी परिलक्षित होती है। उत्पाद स्तर पर यह विस्तार भारत के हाल के कई समझौतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

तालिका-2: हालिया एफटीए के अंतर्गत निर्यातित टैरिफ लाइनों में विस्तार			
बाजार	प्रारंभिक टैरिफ-लाइन कवरेज	नवीनतम टैरिफ-लाइन कवरेज (2025-26)	बढ़ोतरी
संयुक्त अरब अमीरात	7,546 (2021-22)	8,053	6.7%
ऑस्ट्रेलिया	5,396 (2020-21)	5,668	5.0%
मॉरीशस	3,593 (2021-22)	4,345	20.9%
ओमान	2,879 (मई 2026)	3,371 (जून 2026)	17.08%

एफटीए भारतीय वस्तुओं और कौशल को वैश्विक बाजारों से जोड़ते हैं

व्यापारिक वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच में बढ़ोतरी

मौजूदा एफटीए साझेदार देशों की टैरिफ लाइनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से तक तरजीही पहुंच प्रदान करते हैं।

a) पहले से लागू समझौते

- **भारत-ब्रिटेन सीईपीए:** लगभग 99% भारतीय निर्यात ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त प्रवेश कर सकते हैं।
- **भारत-ओमान सीईपीए:** रियायतें ओमान की 98% टैरिफ लाइनों को कवर करती हैं।
- **भारत-ईएफटीए टीईपीए:** 92.2% टैरिफ लाइनें, जो भारत के 99.6% निर्यात का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **भारत-मॉरीशस सीईसीपीए:** 310 भारतीय उत्पाद श्रेणियों को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान की जाती है।
- **भारत-यूई सीईपीए:** यूई की 97% टैरिफ लाइनें, जो भारतीय निर्यात के 99% को कवर करती हैं।
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए:** भारतीय निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनों के 100% पर शुल्क-मुक्त पहुंच।

b) कार्यान्वयन की प्रतीक्षा में समझौते

- **भारत-ईयू एफटीए:** यूरोपीय संघ के 97% टैरिफ लाइनों पर तरजीही व्यवहार, द्विपक्षीय व्यापार मूल्य के लगभग 99.5% को कवर करता है।
- **भारत-न्यूजीलैंड एफटीए:** लागू होने के साथ ही भारतीय निर्यात के 100% हिस्से पर शुल्क-मुक्त पहुंच।

ये समझौते कई श्रम-प्रधान क्षेत्रों में बाजार पहुंच का विस्तार करते हैं। इनमें वस्त्र, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चमड़ा और जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, कालीन और हस्तशिल्प शामिल हैं। इन क्षेत्रों में व्यापक अवसर छोटे उत्पादकों और स्थानीय उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बनाते हैं।

इसके अलावा, सुनियोजित टैरिफ उदारीकरण और संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं किसानों और संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नीतिगत संभावनाएं बनाए रखती हैं।

भारतीय सेवाओं के लिए नए अवसर

वस्तुओं के साथ-साथ, भारत के हालिया एफटीए ने सेवा प्रदाताओं और पेशेवरों के लिए अवसरों का निर्माण किया है। रोजगार, निर्यात और समग्र आर्थिक गतिविधि में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

भारत में रोजगार का लगभग 30% हिस्सा सेवाओं से जुड़ा है। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 में सेवा निर्यात 421.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अपने विशाल आकार को देखते हुए, यह क्षेत्र भारत के एफटीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बाजार पहुंच, पेशेवर गतिशीलता और संबंधित सहायता उपायों से संबंधित प्रमुख प्रतिबद्धताओं को नीचे संक्षेप में बताया गया है।

- भारतीय पेशेवरों के लिए, **भारत-न्यूजीलैंड एफटीए 5,000 कुशल भारतीयों को तीन साल तक रहने के लिए एक निश्चित मार्ग प्रदान करता है।** इसमें आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्माण, आयुष, योग, पाक कला और संगीत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अन्य प्रमुख प्रावधानों में **118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं और 139 क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के लिए एमएफएन व्यवस्था शामिल हैं।** कुशल भारतीयों को **तीन साल तक रहने के लिए एक निश्चित मार्ग प्रदान करता है।** इसमें आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्माण, आयुष, योग, पाक कला और

एमएफएन क्या है?

मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) ट्रीटमेंट एक ऐसा सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत किसी देश के सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।

संगीत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अन्य प्रमुख प्रावधानों में **118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं** और **139 क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के लिए एमएफएन व्यवस्था** शामिल हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: [भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित](#)

- भारत-ईयू एफटीए के अंतर्गत, आईटी/ आईटीईएस, पेशेवर, व्यवसाय, शिक्षा, वित्तीय, पर्यटन और निर्माण सेवाओं सहित **144 सेवा उप-क्षेत्रों** को शामिल किया गया है। अन्य प्रावधानों में व्यावसायिक आगंतुकों और अंतर-निगम स्थानांतरणों की सुगमता, आश्रितों के लिए प्रवेश और कार्य अधिकार शामिल हैं। यह सामाजिक सुरक्षा समझौतों, छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद रोजगार के मौकों के लिए पांच वर्षीय फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: [भारत-ईयू साझेदारी: यूरोपीय संघ के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी](#)

- भारत-यूके सीईटीए के अंतर्गत गतिशीलता प्रावधान आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और शिक्षा क्षेत्र के पेशेवरों को कवर करते हैं। ये व्यावसायिक आगंतुकों, अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरणकर्ताओं, संविदात्मक आपूर्तिकर्ताओं और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए सुगम प्रवेश की अनुमति देते हैं। संबंधित दोगुना योगदान कन्वेंशन सामाजिक सुरक्षा भुगतानों को भी रोकता है, जिससे अनुमानित ₹4,000 करोड़ से अधिक की बचत होती है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: [भारत-यूके सीईटीए लागू हुआ](#)

- भारत-ईएफटीए टीईपीए के तहत, भारतीय सेवा प्रदाताओं को स्विट्जरलैंड के **128 उप-क्षेत्रों**, नॉर्वे के **114**, आइसलैंड के **110** और लिक्टेनस्टीन के **107 उप-क्षेत्रों** में बेहतर पहुंच प्राप्त हुई है। ये अवसर आईटी और व्यवसाय, पेशेवर, शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक सेवाओं तक फैले हुए हैं। इस समझौते में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और वास्तुकला में पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) भी शामिल हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: [भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता: 100 बिलियन डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों को बढ़ावा](#)

- भारत-ओमान सीईपीए के तहत अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरणियों, संविदा आपूर्तिकर्ताओं, व्यावसायिक आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों के अस्थायी प्रवेश और प्रवास की अनुमति दी गई है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: [भारत-ओमान सीईपीए](#)

- भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग **135 सेवा उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं** की हैं। एमएफएन उपचार को आईटी, व्यावसायिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऑडियो-विजुअल सेवाओं सहित **120 उप-क्षेत्रों में** भी विस्तारित किया गया है।
- भारत-यूई सीईसीपीए के तहत, भारतीय सेवा प्रदाताओं को **11 व्यापक क्षेत्रों में लगभग 111 उप-क्षेत्रों तक** पहुंच प्राप्त होती है। इनमें व्यवसाय, संचार, निर्माण, शिक्षा, वित्तीय, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, पर्यावरण और सांस्कृतिक सेवाएं शामिल हैं।
- भारत-मॉरीशस सीईसीपीए **11 व्यापक क्षेत्रों में लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच** प्रदान करता है। इसमें व्यावसायिक, कंप्यूटर, दूरसंचार, वित्तीय, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, ऑडियो-विजुअल और योग सेवाएं शामिल हैं।

भारत की एफटीए यात्रा एक नए कदम की ओर

भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते कार्यान्वयन के गहन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे-जैसे व्यवसाय इन समझौतों के तहत प्राप्त पहुंच का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे, इनका प्रभाव बढ़ता जाएगा। इससे निर्यात में भागीदारी बढ़ेगी, व्यापार में विविधता आएगी और साझेदार बाजारों के साथ वाणिज्यिक संबंध मजबूत होंगे।

हाल ही में हुए समझौतों के कार्यान्वयन के गहन चरण में प्रवेश करने के साथ ही, भारत अपने भावी व्यापार एजेंडे का विस्तार भी कर रहा है। **लगभग दस व्यापार समझौतों पर विचार-विमर्श जारी है**, जिनमें यूरोशियन आर्थिक संघ, पेरू, चिली, इजरायल, कनाडा और मालदीव के साथ नई वार्ताएं शामिल हैं। इसके साथ ही, **भारत-कोरिया सीईपीए** और **भारत-श्रीलंका ईटीसीए** जैसे मौजूदा समझौतों को अपग्रेड किया जा रहा है।

इस विस्तारित नेटवर्क के केंद्र में एक बड़ा वादा निहित है: भारतीयों के उद्यम और आकांक्षाओं को वैश्विक स्तर पर अधिक बाजारों तक ले जाना।

संदर्भ:

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ):

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2216270&lang=1®=3>

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2290437>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284139&lang=2®=48>

https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/Annual_0.pdf

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1810279®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2195127®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1812730®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2248223&lang=1®=3>

<https://www.trade.gov.in/pages/certificate-of-origin>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149736®=48&lang=2>

https://content.dgft.gov.in/Website/HBP_07_2026_Chapter_02.pdf

<https://www.trade.gov.in/pages/about-trade-connect-eplatform>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2267513®=48&lang=2>

https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/final_1.pdf

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288851®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2236134&lang=1®=3>

https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU1405_0GOh6X.pdf

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1821785®=48&lang=2>

विश्व सीमा शुल्क संगठन:

<https://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/faq-origin.aspx#Q6>

विश्व व्यापार संगठन:

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm6_e.htm

विदेश मामलों और व्यापार विभाग (ऑस्ट्रेलिया सरकार):

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/australia-india-ecta/australia-india-ecta-official-text/chapter-4-rules-origin>

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/australia-india-ecta/outcomes/australia-india-ecta-benefits-australia-overview>

पीआईबी अभिलेखागार:

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=154945®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177724®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240065&lang=1®=3>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2233417®=3&lang=1>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एमएम